

टू फगिर टेस्ट

प्रलिस के लयः

सर्वोच्च न्यायालय, वशिव स्वास्थय संगठन

मेन्स के लयः

बलात्कार पीडितों के लयः प्रतगामी कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा है कथित बलात्कार पीडितों का 'टू-फगिर टेस्ट' कराने वालों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा।

टू फगिर टेस्ट:

परचयः

- चकित्सक द्वारा कयः जाने वाले टू-फगिर टेस्ट में पीडिता के जननांगों की संसर्ग संबंधी अभ्यास की जाँच की जाती है।
 - यह अभ्यास अवैज्ञानिक है और कोई वशिषिट जानकारी प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा ऐसी 'सूचना/जानकारी' का बलात्कार के आरोप से कोई लेना-देना नहीं है।
- महला जसिका यौन उत्पीडन हुआ है, उसके स्वास्थय और चकित्सीय जूरतों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्र करने आदिके लयः उसे चकित्सीय परीक्षण से गुजरना पडता है।
- यौन उत्पीडन पीडितों के मामलों से नपिटने के लयः [वशिव स्वास्थय संगठन \(WHO\)](#) द्वारा जारी एक पुस्तिका कहती है, "कौमार्य (या 'टू-फगिर') परीक्षण के लयः कोई जगह नहीं है, इसकी कोई वैज्ञानिक वैधता नहीं है।"

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकनः

- वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय की एकल बेंच ने महिलाओं के एकटवि और पैसवि इंटरकोर्स को आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के तत्त्वों को लागू करने के आलोक में अप्रासंगिक माना।
- न्यायालय ने कहा कजब कोई महिला बलात्कार का आरोप लगाती है तो उसे, उसके यौन रूप से सक्रय होने के कारण बलात्कार न मानना पतिसत्तात्मक और भेदभावपूर्ण का प्रतीक है।
- मई 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कटू फगिर टेस्ट कसीं महिला के नजिता के अधिकार का उल्लंघन करता है और सरकार से यौन शोषण की पुष्टिके लयः बेहतर चकित्सा प्रकरयिा प्रदान करने हेतु आग्रह कयिा था।
- आरथक, सामाजक और सांस्कृतक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अभसिमय, 1966 तथा अपराध के शकार एवं शक्तके दुरुपयोग के पीडितों के लयः न्याय के बुनयिादी सदिधांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1985 का आह्वान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना क बलात्कार पीडिता कानूनी सहायता की हकदार हैं क्योंकि इससे उन्हें नुकसान पहुँचने के साथ इनकी शारीरिक या मानसक अखंडता और गरमा पर आघात होता है।
- अप्रैल 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को टू-फगिर टेस्ट पर प्रतबिंध लगाने का नरिदेश दयिा था।

सरकार के दशा-नरिदेशः

- त्वरति सुनवाई के लयः अपराधक कानून में संशोधन और यौन उत्पीडन के मामलों में बढी सजा पर वचार हेतु गठित जस्टसि वर्मा समति, 2013 की रपिर्ट के बाद केंद्रीय स्वास्थय मंत्रालय ने वर्ष 2014 की शुरुआत में यौन उत्पीडन के शकार लोगों की चकित्सा जाँच हेतु वसितृत दशा-नरिदेश जारी कयि।
- दशानरिदेशों के अनुसार, बलात्कार/यौन हसिा को स्थापति करने के लयः 'टू-फगिर टेस्ट' नहीं कयिा जाना चाहयि।
- दशानरिदेशों में कहा गया है क कसीं भी मेडकिल जाँच के लयः बलात्कार पीडिता (या उसके अभभावक, यदविह नाबालगि/मानसक रूप से वकिलांग है) की सहमत आवश्यक है। सहमतनि देने पर भी पीडिता को आवश्यक इलाज की सुवधा मुहैया कराई जाती है।
- हालाँकयि दशानरिदेश मात्र हैं कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।

आगे की राह

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दशा-नरिदेशों को नज़ि एवं सरकारी अस्पतालों में परचालित कया जाना चाहयि ।
- बलात्कार पीड़िताओं का परीक्षण कयि जाने से रोकने हेतु स्वास्थ्य प्रदाताओं के लयि कार्यशालाएँ आयोजति की जानी चाहयि ।
- इस मुद्दे को डॉक्टरों और पुलसिकर्मयिों दोनों के व्यापक संवेदीकरण एवं प्रशक्तिषण द्वारा संबोधति कयि जा सकता है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: हमें देश में महिलाओं के परतयौन-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं । इस कुकृत्य के वरिद्ध वदियमान वधिकि उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है । इस संकट से नपिटने के लयि कुछ नवाचारी सुझाव दीजयि । (2014)

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/two-finger-test>

